एसजी जयसिंघानी

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका के साथ)

22 फरवरी, 1967

[के. सुभा राव, सी.जे., जे. सी. शाह. एस. एम.शिकरी, वी. रामास्वामी और सी.ए. वैद्यलिंगम]

आयकर सेवा-वरिष्ठता नियम, 1952, आर. 1(एफ)(iii) और (iv)सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के बीच वरिष्ठता-यदि अनुच्छेद का उल्लंघन है। संविधान-प्रचार नियमावली के 14 एवं 16 , आर. 4-श्रेणी 1, ग्रेड II से ग्रेड । तक पदोन्नति - सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए सेवा की अलग-अलग अवधि - भेदभावपूर्ण-आयकर अधिकारी (श्रेणी 1, ग्रेड II) सेवा भर्ती नियम, आर। 4-कोटा निर्धारण- कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य।

1944 में, भारत सरकार ने आयकर सेवा की दो श्रेणियां बनाईं, अर्थात्, ग्रेड 1 और II के साथ वर्ग । सेवा, और ग्रेड II के साथ वर्ग II सेवा। वर्ग I, ग्रेड II में भर्ती की जानी थी: (ए) की जानी थी: (ए) एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से गति वर्ग II, ग्रेड III से। वर्ग II के एक अधिकारी को वर्ग II में 5 साल की सेवा (परिवीक्षा के 2 साल और आयकर अधिकारी के रूप में 3 साल) के बाद वर्ग 1, ग्रेड II में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाता है। 1951 में ,

सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच का अनुपात संभवतः आर के तहत 2: 1 तय किया गया था। आयकर अधिकारी (वर्ग ।, ग्रेड ।।) सेवा भर्ती नियमों के 4। आर के तहत. वरिष्ठता नियम, 1952 के 1 (एफ) (iii), जो सीधे भर्ती किए गए और पदोन्नत लोगों के बीच वरिष्ठता से संबंधित है, एक पदोन्नत व्यक्ति सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ हो जाता है, जिसने उसी वर्ष दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है। विभाग पदोन्नति समिति द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को वर्ग 1 में पदोन्नति की सिफारिश करती है। नियम 1 (एफ) (iv) एक विशेष स्थिति से संबंधित है जिसमें वर्ग ।। सेवा के लिए शुरू में नियुक्त एक अधिकारी को विभागीय पदोन्नति के समान ही वरिष्ठता दी जाती है। यदि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर उसे वर्ग । में नियुक्त किया जाता है।

केंद्रीय राजस्व बोर्ड कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के पदोन्नति नियमों के नियम 4 में कहा गया है कि वर्ग 1, ग्रेड ।। के कार्यालय के लिए ग्रेड 1 में पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा 5 वर्ष की राजपत्रित सेवा है, जिसमें वर्ग । में 1 वर्ष भी शामिल है। ग्रेड ॥ ग्रेड 1 में पदोन्नति के लिए राजपत्रित ।। वर्ष की आयु है , वर्ग ।, ग्रेड । में पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि वास्तव में वर्ग ॥ में 4 वर्ष की सेवा और वर्ग । ग्रेड ॥ में 1 वर्ष की सेवा होगी।

उत्तरदाताओं 4, 5 और 6 को 1947 में श्रेणी II, ग्रेड III सेवा में नियुक्त किया गया था। 1950 की प्रतियोगी परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें और अपीलकर्ता (जो सीधी भर्ती थी) को 1951 में वर्ग 1, ग्रेड II सेवा में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, तीन उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता के वरिष्ठ के रूप में आर के तहत "मानित पदोन्नत" के रूप में दिखाया गया था। 1 (एफ) (आईवी)

अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और तर्क दिया कि (1) आर.- 1 (एफ) (iii) और (iv) वरिष्ठता नियम और आर। पदोन्नति नियमों में से 4 भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले थे। 704 संविधान के 14 और 16 , और (2) कि 1951-56 के दौरान 2:1 के अनुपात को निर्धारित करने वाले कोटा नियम का उल्लंघन करते हुए, पदोन्नत लोगों की अत्यधिक भर्ती की गई थी ।

उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

इस न्यायालय में अपील में,

अभिनिर्धारित : (1) (ए). वरिष्ठता नियम, 1952 का नियम 1 (एफ) (iii), अनुच्छेद के तहत गारंटी का उल्लंघन नहीं करता है। 14 और 16.

यह कहना सही नहीं है कि वर्ग 1, ग्रेड II सेवा में नियुक्त सभी अधिकारियों ने एक वर्ग का गठन किया और एक बार भर्ती होने के बाद अधिकारियों के एक होने के बाद सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। यह वास्तव में दो अलग-अलग स्रोतों से सेवा

में भर्ती और उनके बीच वरिष्ठता के समायोजन का मामला है। पदोन्नति के मामले में समानता की अवधारणा तभी प्रतिपादित की जा सकती है जब पदोन्नत लोगों को एक ही स्रोत से लिया जाए। यदि एक स्रोत का दूसरे के संबंध में अधिमान्य व्यवहार दो स्रोतों के बीच अंतर पर आधारित है , और उक्त मतभेदों का कार्यालय की प्रकृति से उचित संबंध है, तो इसे वैध वर्गीकरण के आधार पर वैध रूप से कायम रखा जा सकता है। वर्तमान मामले में वर्गीकरण का कारण यह था कि सेवा के उच्च स्तर पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। इसे अनुभवी अधिकारियों द्वारा भरा जाना चाहिए जिनके पास न केवल उच्च स्तर की योग्यता हो बल्कि प्रथम श्रेणी का अनुभव भी हो। एक नियम जो काफी अनुभव वाले उत्कृष्ट अधिकारियों को वरिष्ठता देता है और योग्यता के आधार पर चुना जाता है और पदोन्नति को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने वाले प्रतिशत तक सीमित करता है , उसे अनुचित नहीं माना जा सकता है। नियम का शुद्ध प्रभाव यह है कि वर्ग II में 3 साल का उत्कृष्ट कार्य वर्ग I, 'ग्रेड II सेवा' में 2 साल की परिवीक्षा के बराबर है , और मामले के इस पहलू पर विचार करने पर, पदोन्नत व्यक्ति को वरिष्ठता दी जाती है। सीधी भर्ती से एक ही वर्ष में परिवीक्षा अवधि पूरी करना। [711 ईएच; 712 बी, ई, जीएच]

महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे बनाम रंगाचारी[1962] 2 एससीआर 586, 596 का पालन किया गया।

(बी) नियम 1(एफ)(iv) भी उचित वर्गीकरण पर आधारित है और अनुच्छेद के तहत गारंटी का उल्लंघन नहीं करता है । 14 या अनुच्छेद. संविधान की धारा 16(1) . [715 डी]

"मानित पदोन्नत" हमें 1947 में द्वितीय श्रेणी, ग्रेड, द्वितीय श्रेणी की सेवा में नियुक्त किया गया था और वर्ष 1952 तक उस क्लैम में 5 साल की सेवा पूरी की थी और यदि विभागीय पदोन्नति समिति ने तब उनकी सिफारिश की थी, तो उन्हें वर्ग 1 में पदोन्नति दी गई थी। , ग्रेड II, उनमें से प्रत्येक आर के संचालन से अपीलकर्ता से वरिष्ठ हो गया होगा। 1(एफ) (iii).इसके अलावा, यदि सीएल. (iv) अस्तित्व में नहीं होने पर इस प्रकार के प्रमोटी को प्रतिस्पर्धा में बैठने के लिए(iv) अस्तित्व में नहीं होने पर परीक्षा के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा । इसके अलावा, यदि पदोन्नत व्यक्तियों की सेवा द्वितीय श्रेणी में है। ग्रेड III को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और यदि वे शामिल होते हैं वर्ग I, ग्रेड II सेवा में पदोन्नत लोगों की सेवा सीधी भर्ती के रूप में होती है, तो वे
आर के संचालन से दूसरों से कनिष्ठ हो सकते हैं। 1 (एफ) (iii).[715 बी-डी]

(सी) एक बार यह माना जाता है कि आर। वरिष्ठता नियमों का 1 (एफ) (iii) कानूनी रूप से वैध है, पदोन्नति के नियम को सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच किसी भी भेदभाव का कारण नहीं माना जा सकता है। पदोन्नति के नियम का उद्देश्य वास्तव में आर की नीति को क्रियान्वित

करना है। 1-(एफ) (iii) और वर्ग 1, ग्रेड 1 में पदोन्नति के लिए विचार करने से पहले, वर्ग 1, ग्रेड II में ही 5 साल की सेवा की आवश्यकता से इसे पराजित न होने दें । अन्यथा, एक पदोन्नत व्यक्ति को विभागीय द्वारा उपयुक्त प्रमाणित किया जाएगा । 1952 में पदोन्नति समिति-सीधे भर्ती किए गए उन लोगों से वरिष्ठ होगी जिन्होंने उस वर्ष अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन वरिष्ठता एक खाली औपचारिकता होगी, यदि 705 पदोन्नत-अधिकारी को वर्ग II में अपनी सेवा की अवधि की गणना करने की अनुमति नहीं है ग्रेड I में पदोन्नति का उद्देश्य। वर्ग 1, उसे ग्रेड 1, वर्ग I में जाने के लिए 1957 या 1958 तक इंतजार करना होगा , जबकि प्रत्यक्ष भर्तीकर्ता जिन्होंने 1952 या 1953 में अपनी परिवीक्षा पूरी की थी, वे 1955 में ग्रेड I, वर्ग I में जा सकते थे। या 1956 में उन्हें परिवीक्षा पर रखे जाने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि गिनते हुए , [714 ए-डी, जी-एच]

(2) अपीलकर्ता परमादेश की प्रकृति में एक रिट का हकदार था, जिसमें उत्तरदाताओं 1 से 3 को वरिष्ठता को समायोजित करने का आदेश दिया गया था। अपीलकर्ता और अन्य अधिकारी समान रूप से स्थित हैं और कोटा नियम के अनुसार 1951 से 1956 और उसके बाद की अवधि के लिए भर्ती को समायोजित करने के बाद कानून के अनुसार एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए कहा गया है । [718-डी-ई]

आयकर अधिकारियों (वर्ग I, ग्रेड II) सेवा भर्ती नियमों का नियम 4

एक वैधानिक नियम है और इस नियम के तहत सरकार पर एक वैधानिक कर्तव्य है कि वह भरने के उद्देश्य से नियोजित की जाने वाली विधि का निर्धारण करे। रिक्तियां और भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या। नियम के तहत कोटा तय करने के बाद, सरकार के पास स्थिति की तात्कालिकता के अनुसार इसे बदलने या किसी विशेष वर्ष में अपनी इच्छा और खुशी से इसे बदलने का कोई विवेक नहीं रह जाता है। मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन की पहली अनिवार्यता है और विवेकाधिकार, जब कार्यकारी अधिकारियों को दिया जाता है, तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर ही सीमित किया जाना चाहिए। लागू करके किए जाने चाहिए और उनके निर्णय ज्ञात सिद्धांतों और नियमों कोटा नियम जुड़ा हुआ हैवरिष्ठता नियम के साथ और जब तक व्यवहार में कोटा नियम का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, तब तक यह मानना मुश्किल होगा कि वरिष्ठता नियम, यानी वरिष्ठता नियमों का नियम 1(एफ)(iii) और (iv) अनुचित नहीं है। और अनुच्छेद को अपमानित नहीं करता आर्टिकल 16 इसलिए, वर्ग ।।, ग्रेड ।।। से वर्ग 1, ग्रेड ।। सेवा तक, 1951 से 1956 और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित कोटा से अधिक पदोन्नतियों को अवैध रूप से पदोन्नत किया गया माना जाना चाहिए। [717 एच; 718 ए-डी, जी- एच]

[इस आदेश का ऐसे वर्ग ।। अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

जिन्हें स्थायी रूप से सहायक आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। [718 एफ]

भविष्य के वर्षों के लिए सरकार को सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच कोटा निर्धारित करने के लिए एक उचित नियम बनाकर रोस्टर प्रणाली अपनानी चाहिए और रोस्टर को उस क्रम को इंगित करते हुए बनाए रखा जाना चाहिए जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं और पदोन्नति द्वारा, वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित प्रतिशत के अनुसार [719 एफ]

निर्णय: सिविल अपीलीय/मूल क्षेत्राधिकार: 1965 की सिविल अपील संख्या 1038।

1962 की सिविल रिट याचिका संख्या 189-डी में पंजाब उच्च न्यायालय, दिल्ली की सर्किट बेंच के ।। मार्च, 1964 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

और

1966 की रिट याचिका संख्या 5

अनुच्छेद के तहत याचिका भारत के संविधान क 32- मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए।

अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ (1965 के सीए संख्या 1038 में)।

उत्तरदाताओं संख्या 1-3 के लिए एसवी गुप्ते, सॉलिसिटर-जनरल, एनएस बिंद्रा, आर. गणपति अय्यर, आरएच ढेबर और आर. त्यागराजन।

ए.के. सेन, एन.एस. बिंद्रा,-आर. प्रतिवादी संख्या 4 के लिए गणपति अय्यर और आर. त्यागराजन।

उत्तरदाताओं संख्या 5 और 6 के लिए एके सेन, आर. गणपति अय्यर और आर. त्यागराजन।

एलएन श्रॉफ के लिए एमएन श्रॉफ, उत्तरदाताओं संख्या 12, 22, 25, 28, 29, 38, 40, 43, 54, 79, 86, 107 और 117 के लिए।

निरेन डे, अतिरिक्त। सॉलिसिटर-जनरल, आर. गणपति अय्यर और आर. त्यागराजन, उत्तरदाताओं संख्या 20, 116 और 123 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 34 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। हस्तक्षेपकर्ता के लिए आर गोपालकृष्णन, बिशम्बरलाल खन्ना और एचके पुरी।

याचिकाकर्ता के लिए एचआर गोखले, एएसआर चारी, एएन सिन्हा, जेबी दादाचंजी, ओसी माथुर और रविंदर नारायण (1966 के डब्ल्यूपी नंबर 5 में)।

उत्तरदाताओं संख्या 1-4 के लिए एसवी गुप्ते, सॉलिसिटर-जनरल, एनएस बिंद्रा, आर. गणपति लायर, आर.एच. ढेबर और आर. त्यागराजन।

उत्तरदाताओं संख्या 6, 7, 9, 12-17, 19, 22, 24, 26, 30, 31, 35, 37,

41, 42 के लिए एसवी गुप्ते, सॉलिसिटर- जनरल, आर. गणपति लायर, और आर. त्यागराजन। -50, 52-61, 63, 64, 66, 68-70, 7274, 80, 82-85 87, 91, 95 और 96।

हस्तक्षेपकर्ता के लिए एएसआर चारी, आर. गोपालकृष्णन, बिशम्बरलाल खन्ना और एचके पुरी।

न्यायालय का निर्णय रामास्वामी, जे. द्वारा

सिविल अपील संख्या 1038/1965

यह अपील पंजाब उच्च न्यायालय के ।। मार्च 1964 के फैसले से प्रमाण पत्र द्वारा लाई गई है, जिसमें अपीलकर्ता सिविल रिट की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। 1962 की संख्या 189-डी। अनुच्छेद के तहत उनकी याचिका में ।

संविधान के 226, अपीलकर्ता, एसजी जयसिंघानी ने "कोटा" भर्ती के अनुचित कार्यान्वयन के साथ-साथ आयकर सेवा, वर्ग 1, ग्रेड ।। के संबंध में "वरिष्ठता नियम" के रूप में वर्णित संवैधानिक वैधता को चुनौती दी उस सेवा को अनुच्छेद की गारंटी का उल्लंघन करने वाला माना गया है। संविधान के 14 और 16(i). याचिका के मूल प्रतिवादी भारत संघ, सचिव थे। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय राजस्व बोर्ड-प्रतिवादी 1 से 3 के संबंध में। इसके बाद, उत्तरदाताओं 4 से 126 को जोड़ा गया और वे आयकर सेवा में पदोन्नत हैं जो परिणाम से प्रभावित होंगे। याचिका।

आयकर प्रशासन में सुधार के लिए, भारत सरकार ने 29 सितंबर, 1944 को मौजूदा आयकर सेवाओं को वर्ग । और ।। के रूप में पुनर्गठित और वर्गीकृत किया। आयकर अधिकारियों, वर्ग । की भर्ती के लिए पुन: संगठनात्मक योजना प्रदान की गई। ग्रेड ।। सेवा आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा। पुनर्गठन योजना भारत सरकार, वित्त विभाग (केंद्रीय राजस्व) के पत्र दिनांक 29 सितंबर, 1944 (उदा. बी) में निर्धारित की गई थी। इसने आयकर सेवा की दो श्रेणियां बनाईं, ग्रेड । और ग्रेड ।। के साथ वर्ग । और ग्रेड 111 के साथ वर्ग ।। सेवा। वर्ग । ग्रेड ।। सेवा में भर्ती की जानी थी: (ए) एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और (बी) वर्ग आईटी ग्रेड ।।। से पदोन्नति द्वारा, पत्र के पैराग्राफ 2 (डी) में निर्धारित अनुपात सीधी भर्ती द्वारा 80% और वर्ग ।। ग्रेड ।।। सेवा से पदोन्नति द्वारा 20% है, और यदि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार थे पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं होने पर, अधिशेष रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग) के पत्र दिनांक 24 जनवरी 1950 (रिट याचिका के पूर्व जी) में वरिष्ठता के नियम निर्धारित किये गये थे। इन नियमों में निर्धारित किया गया है- वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सिद्धांत (ए) संयुक्त प्रतिस्पर्धी परीक्षा के परिणाम पर भर्ती किए गए सीधी भर्ती के बीच; (बी) वर्ग ।। से चयनित पदोन्नतियों के बीच और (सी) सीधे भर्ती किए गए लोगों के बीच जो किसी दिए गए वर्ष में अपनी परिवीक्षा पूरी करते हैं और वर्ग 1 में

नियुक्ति के लिए उसी वर्ष में पदोन्नत होते हैं। इन नियमों को 5 सितंबर, 1952 को संशोधित किया गया था। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व प्रभाग, पत्र क्रमांक एफ क्रमांक 58(3)-विज्ञापन. ।T/50, दिनांक 5 सितंबर, 1952। प्रासंगिक नियम, अर्थात, नियम । (एफ) जैसा कि 1950 में बनाया गया था, इस प्रकार था:-

"1944 में संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों पर भर्ती किए गए सीधे भर्ती की वरिष्ठता , और बाद के वर्षों की गणना इस प्रकार की जाएगी:-

(i) पिछली परीक्षा में सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों को बाद की परीक्षा से भर्ती किए गए लोगों से ऊपर रैंक दिया जाएगा।

(ii) किसी एक परीक्षा में सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों को उस परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त रैंक के अनुसार परस्पर रैंक दी जाएगी।

(iii) किसी भी कैलेंडर वर्ष में आयोग द्वारा प्रमाणित किए गए पदोन्नत व्यक्ति सभी एम 2 एसयूपी से वरिष्ठ होंगे। सीधी भर्ती वाले वे लोग जो उस वर्ष या उसके बाद अपनी परिवीक्षा पूरी करते हैं और उस वर्ष या उसके बाद की किसी तारीख से उनकी पुष्टि की जाती है।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति शुरू में वर्ग ।। आयकर अधिकारी के रूप में भर्ती हुआ हो, लेकिन बाद में संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के परिणामों पर वर्ग । में नियुक्त किया गया हो, यदि

उसने वर्ग । सेवा में अपनी नियुक्ति से पहले आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।, वरिष्ठता के उद्देश्य से पदोन्नत समझा जाएगा।"

1952 में संशोधित नियम निम्नलिखित प्रभाव वाला था।

"1944 में संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं और उसके बाद के वर्षों के परिणामों पर भर्ती किए गए सीधी भर्ती की वरिष्ठता निम्नानुसार मानी जाएगी

(i) पिछली परीक्षा में सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों को बाद की परीक्षा में भर्ती किए गए लोगों से ऊपर रैंक दिया जाएगा।

(ii) किसी एक परीक्षा में सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों को उस परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त रैंक के अनुसार परस्पर रैंक दी जाएगी;

(iii) विभागीय पदोन्नति समिति की अगली बैठक से पहले विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार पदोन्नत अधिकारी कैलेंडर के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों पर नियुक्त सभी सीधी भर्ती से वरिष्ठ होंगे। वह वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई और पिछले तीन वर्ष।

(iv) (iii) खंड (iii) में निहित किसी भी बात के बावजूद, संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर बाद में वर्ग ।। के आयकर अधिकारी को वर्ग । में नियुक्त किया जाएगा, यदि उसने अपने पहले आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्रथम

श्रेणी सेवा में नियुक्ति को वरिष्ठता के उद्देश्य से पदोन्नत माना जाएगा।"

1952 के नियम का खंड (iv) लगभग 1950 में बनाए गए नियम के खंड (iii) के परंतुक का पुनरुत्पादन है और खंड (iii) को कुछ अलग भाषा में पुनर्गठित किया गया है, हालांकि सार रूप में इसमें खंड का मुख्य भाग शामिल है (iii) 1950 के नियम में कहा गया है। उपवाक्य का प्रभाव (iii) 1952 का नियम यह है कि पदोन्नत व्यक्ति सीधी भर्ती से वरिष्ठ हो जाता है, जिसने उसी वर्ष दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति वर्ग ।। के अधिकारियों को वर्ग 1 में पदोन्नति के लिए सिफारिश करने के लिए बैठक करती है। निम्नलिखित उदाहरण नियम के अनुप्रयोग को स्पष्ट करते हैं:

उदाहरण 'ए'					
प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का वर्ष	परिवीक्षा के दो वर्ष पूरे होने का वर्ष	विभागीय प्रचार समिति	सीधी भर्ती की स्थिति	प्रमोटीस वरिष्ठता

1	2	3	4	5	6
1947 तीन पिछले वर्ष	1948	1950		आपने परिवीक्षा पूरी कर ली है	सीनीयर
1948	1949	1951		परिवीक्षा पूरी नहीं की है	
1949	1950	1952		परिवीक्षा पूरी नहीं की है	करना
1950	1951	1953	1950	करना	करना

उदाहरण 'बी'					
1	2	3	4	5	6
1950 तीन पिछले वर्ष	1951	1953		आपने परिवीक्षा पूरी कर ली है	सीनीयर
1951	1952	1954		परिवीक्षा पूरी नहीं की है	करना
1952	1953	1955		करना	करना
1953	1954	1956	1953 में	करना	करना

एक वर्ग ।। अधिकारी को जब सीधे भर्ती किया जाता है तो उसे दो साल तक परिवीक्षा पर रहना पड़ता है, इस अवधि के दौरान उसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के एक कोर्स से गुजरना पड़ता है और पुष्टि होने के लिए एक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। आयकर अधिकारी के रूप में काम करने की न्यूनतम अवधि (दो साल की परिवीक्षा के बाद) के बाद उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ग 1 में पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। कहने का मतलब है कि उन्हें न्यूनतम सेवा करनी होगी वर्ग ।, ग्रेड ।। सेवा में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य

होने से पहले वर्ग II में कुल मिलाकर 5 वर्ष। नियम 1(एफ) का खंड (iv) एक विशेष स्थिति से संबंधित है जिसमें वर्ग II सेवा के लिए शुरू में नियुक्त एक अधिकारी को विभागीय पदोन्नत के समान वरिष्ठता दी जाती है यदि वर्ग II में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसे नियुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर वर्ग I तक।

18 अक्टूबर, 1951 को 29 सितंबर, 1944 की पुनर्संगठन योजना के तहत 80'/ और 20% के भर्ती कोटा को संशोधित किया गया था। संशोधित भर्ती कोटा नियम 66 के तहत ग्रेड II वर्ग I में रिक्तियों का 2/3% सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और शेष 33-1/3% ग्रेड III वर्ग II सेवा से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। कोई भी अतिरिक्त रिक्तियां जो उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण पदोन्नति द्वारा नहीं भरी जा सकती थीं, उन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटे में जोड़ा जाना था।

केंद्रीय राजस्व बोर्ड कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के पृष्ठ 251 पर पदोन्नति के नियमों का नियम 4 भी इस अपील में विवाद का विषय रहा है और नीचे दिया गया है।

> "आयकर अधिकारी, वर्ग I (ग्रेड 1) - इस ग्रेड में पदोन्नति आयकर अधिकारी वर्ग 1, ग्रेड II के ग्रेड से की जाती है। पदोन्नति फिटनेस के अधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती है,

न कि चयन द्वारा आम तौर पर वर्ग II से वर्ग I के ग्रेड II में पहली बार में ही पदोन्नति की जाती है। हालाँकि, आयकर सेवाओं के पुनर्गठन के शुरुआती चरणों में, कई वरिष्ठ अधिकारियों को वर्ग II से सीधे वर्ग 1 में पदोन्नत किया गया था। , ग्रेड 1, लेकिन ऐसी पदोन्नति आमतौर पर भविष्य में नहीं होगी।

ध्यान दें - संघ लोक सेवा आयोग ने फैसला सुनाया है कि कार्यवाहक आईटीओ के वर्ग 1, ग्रेड I, वर्ग 1, ग्रेड II में पदोन्नति - जिसका उसमें प्रतिधारण है विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदित ग्रेड भी आईटीओ, वर्ग II, ग्रेड III से आईटीओ, वर्ग 1, ग्रेड I में पदोन्नति की प्रकृति में होगा और आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी, भले ही आईटीओ, वर्ग 1 से पदोन्नति, ग्रेड II से वर्ग 1, ग्रेड I विभागीय पदोन्नति समिति के संदर्भ के बिना वरिष्ठता सह-फिटनेस के आधार पर बनाया जाता है। इसलिए, क्लास I, ग्रेड I की नियुक्तियों को अनुमोदन के लिए आयोग को भेजा जाना चाहिए, जब तक कि अधिकारियों को क्लास 1, ग्रेड II पद पर पुष्टि नहीं की जाती है।

पदोन्नति का आधार वरिष्ठता-सह-फिटनेस है और निर्धारित न्यूनतम सेवा पांच साल की राजपत्रित सेवा है जिसमें वर्ग 1, ग्रेड II में एक वर्ष शामिल है।"

पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियम 1(एफ)(iii) और (iv), 1952 में निर्धारित सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धांत भेदभावपूर्ण नहीं थे और इसमें भेदभाव नहीं था। अनुच्छेद का कोई उल्लंघन नहीं. संविधान के 14 और 16(1). पूर्ण पीठ द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा घोषित कोटा नियम केवल एक नीतिगत बयान था और इसमें कोई वैधानिक बल नहीं था और कोटा से हटने से किसी भी न्यायसंगत मुद्दे का जन्म नहीं हुआ। आगे यह देखा गया कि वर्ग I, ग्रेड II से वर्ग 1, ग्रेड I तक पदोन्नति नियम भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद के अधिकार के बाहर नहीं था। संविधान के 14 और 16.

इस अपील में विचार किया जाने वाला पहला प्रश्न यह है कि क्या 1952 में बनाए गए वरिष्ठता नियमों का नियम 1(एफ)(iii) अनुच्छेद के तहत गारंटी का उल्लंघन करता है। संविधान के 14 और 16. अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि विवादित नियम सीधी भर्ती और पदोन्नति के बाद उनके बीच अनुचित वर्गीकरण पर आधारित था। वर्ग 1, ग्रेड II सेवा और उस वर्गीकरण के आधार पर पदोन्नत लोगों को उसी वर्ष और पिछले तीन वर्षों की सीधी भर्ती पर वेटेज के साथ वरिष्ठता दी जाती है। यह तर्क दिया गया कि भर्ती के बाद वर्ग 1, ग्रेड II सेवा के अधिकारियों के बीच भेदभाव किया गया था और नियम के वास्तविक

कामकाज में सीधी भर्ती करने वालों को नीचे धकेला जाता था और वर्ग । सेवा में उच्च पदों पर पदोन्नति की उनकी संभावनाओं को स्थगित किया जाता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि क्लास 1, ग्रेड ॥ सेवा में नियुक्त सभी अधिकारियों ने एक वर्ग का गठन किया है और अधिकारियों की एक बार भर्ती होने के बाद सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया कि पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले लोग प्रवेश के तुरंत बाद एक वर्ग बन जाते हैं और उसके बाद उस वर्ग के भीतर कोई वर्ग नहीं हो सकता है। ,हम अपीलकर्ता के तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। हमारी राय में, इस समस्या से इस तरह निपटना सही नहीं है जैसे कि यह पदोन्नति के उद्देश्य से एक सेवा को दो वर्गों में वर्गीकृत करने का मामला है, और पदोन्नति नियम दो वर्गों में से एक को नुकसान पहुंचाने वाला है। यह वास्तव में दो अलग-अलग स्रोतों से सेवा में भर्ती और फिर दो स्रोतों से आने वाले भर्तीकर्ताओं के बीच वरिष्ठता के समायोजन का मामला है। जहाँ तक अनुच्छेद की बात है. 16(1) का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता कि वरिष्ठता का नियम अनुचित आधार पर आगे बढ़ता है। वर्गीकरण का उद्देश्य आयकर सेवा के उच्च पदों को अनुभवी अधिकारियों द्वारा भरना है जिनके पास न केवल उच्च स्तर की योग्यता है बल्कि प्रथम श्रेणी का अनुभव भी है। इस मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उनकी राय है कि कोटा नियम के साथ पढ़ने पर वरिष्ठता नियम अनुचित नहीं है, जो एक विशेष

समिति द्वारा चुने गए पदोन्नत लोगों के लिए पदों के एक छोटे प्रतिशत के विशेष आरक्षण का प्रावधान करता है, जो पदोन्नति के बाद उम्मीदवारों की फिटनेस निर्धारित करता है। आयकर अधिकारी के रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो। एक नियम जो काफी अनुभव वाले उत्कृष्ट अधिकारियों को वरिष्ठता देता है, और योग्यता के आधार पर चुना जाता है और पदोन्नति को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने वाले प्रतिशत तक सीमित करता है, उसे अनुचित नहीं माना जा सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, वर्ग 1, ग्रेड II सेवा में शामिल होने वाले सीधे भर्तीकर्ताओं को दो साल की प्रशिक्षण अवधि से गुजरना पड़ता है और उसके बाद वे पुष्टि के लिए योग्य हो जाते हैं। वर्ग II, ग्रेड III की परिवीक्षा अवधि के दौरान पहले से ही समान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला एक पदोन्नत व्यक्ति, आयकर विभाग के मूल्यांकन और कार्य अनुभव की तीन साल की अवधि के साथ वर्ग 1, ग्रेड II में शामिल होता है। यह जोड़ना आवश्यक है कि वर्ग I में पदोन्नत व्यक्ति का चयन योग्यता के आधार पर होता है और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उत्कृष्ट योग्यता, काम के रिकॉर्ड और उम्मीदवार की क्षमता को बहुत महत्व दिया जाता है, ताकि जो लोग आते हैं वर्ग 1, ग्रेड II वे अधिकारी हैं जिन्होंने वर्ग II सेवा में आयकर अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट क्षमता दिखाई है। 1966 की रिट याचिका संख्या 5 में उत्तरदाताओं 1 से 4 की ओर से हलफनामे के अनुलग्नक 2 में दिए गए बयान से पता चलता है कि चयन के मानक बहुत कठोर हैं क्योंकि चयन के लिए विचार

किए गए अधिकारियों का बहुत छोटा हिस्सा वास्तव में पदोन्नत किया जाता है। नियम 1(एफ)(iii) का शुद्ध प्रभाव यह है कि वर्ग ।। में तीन साल का उत्कृष्ट कार्य वर्ग । सेवा में दो परिवीक्षा के बराबर है और मामले के इस पहलू पर विचार करने पर पदोन्नत व्यक्ति को वरिष्ठता दी जाती है। सीधी भर्ती से एक ही वर्ष में परिवीक्षा अवधि पूरी करना।

इस विषय पर प्रासंगिक कानून अच्छी तरह से स्थापित है। अनुच्छेद के तहत संविधान के 16 के अनुसार, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति या एक कार्यालय से उच्च पद पर पदोन्नति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। संविधान का अनुच्छेद 16 अनुच्छेद में निहित समानता की अवधारणा के अनुप्रयोग की एक घटना मात्र है । उसके 14 . यह नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में समानता के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि नियुक्ति या पदोन्नति के उद्देश्य से कर्मचारियों का उचित वर्गीकरण हो सकता है। पदोन्नति के मामले में समानता की अवधारणा तभी प्रतिपादित की जा सकती है जब पदोन्नतियों को एक ही स्रोत से लिया जाए। यदि एक स्रोत का दूसरे के संबंध में अधिमान्य व्यवहार उक्त दो स्रोतों के बीच अंतर पर आधारित है, और उक्त मतभेदों का उस कार्यालय या कार्यालयों की प्रकृति से उचित संबंध है जहां भर्ती की जाती है, तो उक्त भर्ती की जा सकती है। वैध वर्गीकरण के आधार पर वैध रूप से कायम रखा जाए। अनुच्छेद की सुरक्षा की सीमा से निपटना । संविधान के 16(1)

के अनुसार, इस न्यायालय ने महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे बनाम रंगाचारी (1) में कहा,

"यह स्पष्ट होगा कि रोजगार से संबंधित मामले केवल रोजगार के कार्य से पहले प्रारंभिक मामलों तक ही सीमित नहीं हो सकते हैं। संकीर्ण निर्माण अनुच्छेद 16 (1) के अनुप्रयोग को प्रारंभिक रोजगार तक ही सीमित रखेगा और कुछ नहीं; लेकिन यह स्पष्ट रूप से रोजगार से संबंधित मामलों में से केवल एक है। रोजगार से संबंधित अन्य मामले अनिवार्य रूप से वेतन और प्रावधान होंगे इसमें आवधिक वेतन वृद्धि, छुट्टी, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में शर्तें। ये सभी रोजगार से संबंधित मामले हैं और इन्हें संबंधित अभिव्यक्ति के मामलों में शामिल किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 16(1) में रोजगार के लिए । अनुच्छेद 16(1) हमारे द्वारा बताए गए रोजगार के साथ-साथ किसी भी कार्यालय में नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है। हमें। तीन प्रावधान अनुच्छेद। 16(1), अनुच्छेद. 14 और अनुच्छेद. 15(1) गारंटी के समान संवैधानिक कोड का हिस्सा बनें और एक दूसरे के पूरक बनें। यदि ऐसा है, तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि रोजगार से संबंधित मामलों में रोजगार से संबंधित सभी मामले शामिल होने चाहिए। इसके बाद, रोजगार के लिए जो रोजगार के लिए प्रासंगिक हैं और ऐसे रोजगार के नियमों और शर्तों का हिस्सा बनते हैं।"

इस न्यायालय ने उस मामले में आगे कहा,

" अनुच्छेद 16(2)। भेदभाव पर रोक लगाता है और इस प्रकार अनुच्छेद 16(1) द्वारा गारंटीकृत अवसर की समानता के मौलिक अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन का आश्वासन देता है। शब्द, केवल रोजगार के संबंध में इसलिए, अनुच्छेद 16(2) में प्रयुक्त , अनुच्छेद 16(1) में निर्दिष्ट रोजगार से संबंधित सभी मामले शामिल होने चाहिए । इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि चयन पदों पर पदोन्नति अनुच्छेद 16(1) के तहत दोनों शामिल है। और (2)।"

हम आगे अपीलकर्ता के तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि । आयकर अधिकारी वर्ग 1, ग्रेड II से वर्ग 1, ग्रेड । तक पदोन्नति का नियम चरित्र में भेदभावपूर्ण है। यह तर्क दिया गया था कि सीधी भर्ती के लिए आयकर अधिकारी वर्ग 1, ग्रेड II के रूप में 5 साल बिताने होते हैं, जबकि एक पदोन्नत अधिकारी को ग्रेड 1 में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा के साथ वर्ग I, ग्रेड II और अन्य चार साल की सेवा देनी होती है। वर्ग II, ग्रेड III में गिना जा रहा है। यह इसलिए प्रस्तुत किया गया कि नियम भेदभावपूर्ण तरीके से सीधी भर्ती के खिलाफ संचालित होता है। हमारी राय में अपीलकर्ता के तर्क में कोई दम नहीं है। एक बार जब यह माना जाता है कि नियम 1(एफ)(iii) में अधिनियमित वरिष्ठता का नियम कानूनी रूप से वैध है, तो पदोन्नति का नियम यानी, सीएच का नियम 4। केंद्रीय राजस्व बोर्ड कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के IX को सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों

के बीच किसी भी तरह के भेदभाव का कारण नहीं माना जा सकता है। नियम 4 में कहा गया है कि श्रेणी 1, ग्रेड ।। अधिकारी के लिए उस सेवा के ग्रेड । में पदोन्नति के मामले में निर्धारित न्यूनतम सेवा पांच साल की राजपत्रित सेवा है, जिसमें वर्ग 1, ग्रेड ।। में एक वर्ष भी शामिल है। इसलिए एक पदोन्नत व्यक्ति के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि वर्ग ।, ग्रेड । में पदोन्नति के लिए वास्तव में वर्ग ।।, ग्रेड ।।। में 4 साल की सेवा और वर्ग 1, ग्रेड ।। में एक वर्ष की सेवा है। नियम का उद्देश्य वास्तव में नियम 1 (एफ) (iii) की नीति को पूरा करना है () वरिष्ठता के नियम और इसे वर्ग ।, ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार से पहले वर्ग 1, ग्रेड ।। में पांच साल की सेवा की आवश्यकता से पराजित होने की अनुमति न दें। पदोन्नत व्यक्ति को सीधी भर्ती से वरिष्ठ पद पर रखा जाता है, जो उस वर्ष परिवीक्षा पूरी करता है जिसमें पदोन्नत व्यक्ति का चयन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाता है। यदि यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वर्ग ।। में आयकर अधिकारी के रूप में पिछली सेवा को गिना नहीं जाना है, तो नियम 1 (एफ) (iii) रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सीधे भर्ती किए गए अधिकारी जो पदोन्नत लोगों से कनिष्ठ हैं वे ग्रेड । में जाएंगे। प्रमोटी अधिकारियों से पहले. उदाहरण के लिए, 1952 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा फिट प्रमाणित एक पदोन्नत व्यक्ति उस वर्ष में अपनी परिवीक्षा पूरी करने वाले सीधी भर्ती से वरिष्ठ होगा। और यदि यह निर्धारित किया जाना है कि पदोन्नत अधिकारी ग्रेड 1, वर्ग । में पदोन्नति के उद्देश्य

से वर्ग ।। में अपनी सेवा की अवधि की गणना नहीं करेगा, तो उसे ग्रेड 1, वर्ग 1 में जाने के लिए 1957 या 1958 तक इंतजार करना होगा। , जबकि सीधे भर्ती किए गए लोग जिन्होंने 1952 या 1953 में अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली थी, वे 1955 या 1956 में ग्रेड 1, वर्ग 1 में चले गए होंगे, उस तारीख से पांच साल की अवधि की गणना की जाएगी जिस दिन उन्हें परिवीक्षा पर रखा गया था। इस विसंगति को दूर करने के लिए पदोन्नति नियम बनाया गया है और हम अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस नियम के संचालन में कोई भेदभाव है। पदोन्नति का नियम ग्रेड ।। में वेटेज और वरिष्ठता के नियम के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पदोन्नति के नियम में ग्रेड ।।। में सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाना है, तो ग्रेड ।। में वरिष्ठता एक खाली औपचारिकता होगी।

वरिष्ठता नियमों के नियम 1(एफ)(iv) के संबंध में, केवल तीन उत्तरदाता हैं यानी, उत्तरदाता 4, 5 और 6 जिन्हें नियम के इस खंड के तहत "मानित पदोन्नत" के रूप में पदोन्नत किया गया है। उनमें से प्रत्येक को 1947 में वर्ग ।।, ग्रेड ।।। सेवा में नियुक्त किया गया था और वर्ष 1950 की प्रतियोगी परीक्षा में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद 1951 में वर्ग 1, ग्रेड ।। सेवा में नियुक्त किया गया था, उसी वर्ष जिसमें अपीलकर्ता सफल हुआ था। अपीलकर्ता 1951 में वर्ग 1, ग्रेड ।। सेवा में भी शामिल हुआ वरिष्ठता सूची में तीन उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता से वरिष्ठ दर्शाया गया है। अपीलकर्ता की आपत्ति यह है कि जबकि वे एक ही

प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, कृत्रिम नियम के संचालन के कारण वे उनसे वरिष्ठ हो गए थे, जिसके द्वारा उन्हें "मानित पदोन्नत" माना जाता है; अन्यथा वे उनसे कनिष्ठ बने रहते। इन उत्तरदाताओं की ओर से श्री बिंद्रा द्वारा यह तर्क दिया गया कि उन्हें 1947 में वर्ग ।।, ग्रेड ।।। सेवा में नियुक्त किया गया था और वर्ष 1952 तक उस श्रेणी में 5 साल की सेवा पूरी कर ली थी और यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 1953 में हुई थी, जैसा कि वास्तव में बैठक हुई, और यदि इसने वर्ग ।, ग्रेड ।। में उनकी पदोन्नति की सिफारिश की, तो उनमें से प्रत्येक सीएल के संचालन से अपीलकर्ता से वरिष्ठ हो गया होगा। (iii) नियम 1(एफ) के लिए। आगे इस बात पर भी विचार किया गया कि यदि नियम 1(एफ)(iv) मौजूद नहीं होता तो इस प्रकार के प्रमोटी को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि वर्ग ।।, ग्रेड ।।। में पदोन्नत लोगों की सेवा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है और यदि वे सीधे भर्ती के रूप में वर्ग 1, ग्रेड ।। सेवा में शामिल हो जाते हैं तो वे खुद को पीछे छूट गए लोगों से कनिष्ठ बन सकते हैं। नियम 1(एफ)(iii) के संचालन द्वारा वर्ग ।।, ग्रेड ।।। सेवा में। तदनुसार हमारी राय है कि नियम 1(एफ)(iv) उचित वर्गीकरण पर आधारित है और अनुच्छेद के तहत गारंटी का उल्लंघन नहीं करता है। 14 या अनुच्छेद. संविधान की धारा 16(1) .

हम इस अपील में विचार के लिए उठने वाले अगले प्रश्न पर विचार

करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात। अपीलकर्ता का आरोप है कि कोटा नियम का उल्लंघन कर पदोन्नत लोगों की अत्यधिक भर्ती की गई। आयकर अधिकारी (वर्ग 1, ग्रेड ।।) सेवा भर्ती नियमों का नियम 3 निम्नलिखित प्रभाव वाला है

"सेवा में निम्नलिखित तरीकों से भर्ती की जाएगी :-

(i) इन नियमों के भाग ।। के अनुसार भारत में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।

(ii) इन नियमों के भाग ।।। के अनुसार ग्रेड H। (वर्ग ।। सेवा) से चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा।"

नियम 4 में लिखा है,

"नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, सरकार किसी विशेष रिक्तियों, या ऐसी रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से नियोजित की जाने वाली विधि या तरीकों का निर्धारण करेगी, जिन्हें किसी विशेष अवधि के दौरान भरने की आवश्यकता हो सकती है, और उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक विधि द्वारा भर्ती किया जाना है।"

नियम 5 में कहा गया है :

"सेवा में रिक्तियां जो पदोन्नति के अलावा अन्यथा भरी जाती हैं, उन्हें भारत सरकार (गृह विभाग) के संकल्प संख्या एफ. 14/17-बी/ के

प्रावधानों के अनुसार भारत में विभिन्न समुदायों के बीच विभाजित किया जाएगा। 33-स्था. दिनांक 4 जुलाई, 1934 (सेवाओं में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंध में) और संख्या 23/5/42-स्था. (एस) दिनांक ।। अगस्त, 1943 (सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में) और अनुपूरक निर्देश रीविथ से जुड़े थे।"

भारत सरकार के 29 सितंबर 1944 के पत्र (अपीलकर्ता की रिट याचिका के लिए पूर्व बी) में कहा गया है कि वर्ग । के ग्रेड ।। में भर्ती आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी और " ग्रेड में उत्पन्न होने वाली 80% रिक्तियां भारतीय लेखा परीक्षा और संबद्ध सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और शेष 20% रिक्तियां चयन द्वारा पदोन्नति के आधार पर भरी जाएंगी, बशर्ते पदोन्नति के लिए उपयुक्त संख्या में पुरुष उपलब्ध हों। . पत्र में यह भी कहा गया था कि यदि कोई रिक्तियां हैं जिन्हें उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव में पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता है, तो उन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटे में जोड़ा जाएगा। बाद में भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर, 1951 के अपने पत्र में कोटा में बदलाव किया गया (उदा. ई से रिट याचिका तक)। इस पत्र में भारत सरकार ने कहा कि. उन्होंने परामर्श से निर्णय लिया था। संघ लोक सेवा आयोग के साथ पांच साल की अवधि के लिए, पहली बार में, वर्ग 1, ग्रेड ।। में 66-2/3% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और शेष 33-1/3% रिक्तियां सीधी भर्ती से भरी

जाएंगी। पदोन्नति के आधार पर और कोई अतिरिक्त रिक्तियां जो उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण नहीं भरी जा सकतीं, उन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटे में जोड़ा जाएगा। ,.इस मामले में, वर्ष 1945 और 1950 के बीच नियम के संचालन के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है, हालांकि याचिका में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन वर्षों में भी पदोन्नत लोगों की अत्यधिक भर्तियां हुईं। प्रतिवादी नंबर 1 के हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि ये आयकर सेवा के प्रारंभिक वर्ष थे और विभाग का पुनर्गठन पूरा हो रहा था और पुनर्गठन की प्रारंभिक अवधि 1950 तक चली। तर्क वर्षों तक ही सीमित था 1951 से 1956। अपीलकर्ता के अनुसार, कोटा नियम द्वारा अनुमत संख्या से अधिक 71 पदोन्नत लोगों की अत्यधिक भर्ती की गई थी। अपील के तहत फैसले में उच्च न्यायालय ने मामले की जांच की और पाया कि 1951 से 1954 तक चार वर्षों के लिए पदोन्नति की अतिरिक्त संख्या 31 थी। अपील की सुनवाई के दौरान हमने वित्त मंत्रालय के सचिव को आदेश दिया था कि 1945 के बाद से वर्ष दर वर्ष उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की प्रकृति - स्थायी या अस्थायी और रिक्तियों की श्रृंखला और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करें जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों से प्रासंगिक हैं। 31 जनवरी, 1967 को अपने हलफनामे में श्री आरसी दत्त ने कहा कि वह अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या का पता लगाने में सक्षम नहीं थे। हालाँकि, एक बयान, उदा. ई,

प्रासंगिक वर्षों के दौरान प्रथम श्रेणी सेवा में भर्ती के दो तरीकों से भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया था

वर्ष	यूपीएससी परीक्षा. उम्मीदवारों	युद्ध सेवा चयनित	वर्ग ।। से अधिकारी
1951	50	-	-
1952	-	2	49
1953	52	-	38
1954	44	-	30
1955	45	-	24
1956	-	-	25

यह "श्री आर., सी. दत्त के हलफनामे से स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नगत वर्षों के लिए कोटा नियम का सख्ती से पालन किया गया था या नहीं। के जवाबी हलफनामे में 1966 की रिट याचिका संख्या 5 में उत्तरदाताओं 1 से 4 में

हालांकि एक दावा है कि कोटा नियम का "काफी हद तक अनुपालन किया गया है।"

उत्तरदाताओं 1, 2 और 3 की ओर से सॉलिसिटर-जनरल ने प्रस्तुत किया कि कोटा नियम केवल नियम में बताए गए अनुपात में दो अलग-अलग स्रोतों से भर्ती निर्धारित करने के लिए एक प्रशासनिक निर्देश था और उस कोटा नियम का उल्लंघन एक न्यायसंगत मुद्दा नहीं था। . सॉलिसिटर-जनरल ने कहा कि हालाँकि, कोटा नियम का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। लेकिन वर्ग 1, ग्रेड में स्थायी रिक्तियों के आंकड़ों के अभाव में; II संबंधित वर्षों में सॉलिसिटर-जनरल यह बताने में असमर्थ थे कि नियम से किस हद तक विचलन हुआ है। हम सॉलिसिटर-जनरल के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कोटा नियम सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह विवादित नहीं है कि आयकर अधिकारी (वर्ग 1, ग्रेड II) सेवा भर्ती नियमों का नियम 4 एक वैधानिक नियम है और इस नियम के तहत सरकार पर एक वैधानिक कर्तव्य है कि वह विधि या तरीकों का निर्धारण करे। रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए नियोजित किया जाए और। प्रत्येक विधि द्वारा भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या। भारत सरकार के 18 अक्टूबर, 1951 के पत्र में नियम 4 का कोई विशेष संदर्भ नहीं है, लेकिन उनके पत्र में निर्धारित कोटा भारत सरकार द्वारा नियम के तहत दी गई वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए तय किया गया माना जाना चाहिए। 4. नियम 4 के तहत उस पत्र में कोटा तय करने के बाद,

अब भारत सरकार के लिए यह कहना खुला नहीं है कि प्रत्येक वर्ष के लिए कोटा का पालन करना उसके लिए बाध्य नहीं है और वह कोटा में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है। विशेष स्थिति का विवरण (1966 की रिट याचिका संख्या 5 में उत्तरदाताओं 1 से 3 के जवाबी हलफनामे का पैरा 24 देखें)। हमारी राय है कि भर्ती के दो स्रोतों के बीच नियम 4 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोटा तय करने के बाद, भारत सरकार के पास स्थिति की तात्कालिकता के अनुसार उस कोटा को बदलने या इससे विचलित होने का कोई विवेक नहीं बचा है। कोटा, किसी विशेष वर्ष में, अपनी इच्छा और खुशी से। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, कोटा नियम वरिष्ठता नियम से जुड़ा हुआ है और जब तक कोटा नियम का व्यवहार में सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, तब तक वरिष्ठता नियम यानी नियम 1(एफ) (iii) और (iv) को मानना मुश्किल होगा।), अनुचित नहीं है और अनुच्छेद का अपमान नहीं करता है । 16 संविधान का. तदनुसार हमारी राय है कि 1951 से 1956 और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित कोटा से अधिक में वर्ग 2, ग्रेड 3 से वर्ग 1, ग्रेड 2 सेवा में पदोन्नत लोगों को अवैध रूप से पदोन्नत किया गया है और अपीलकर्ता एक रिट का हकदार है। अपीलकर्ता और उसके जैसे अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता को समायोजित करने और 1951 से 1956 और उसके बाद की अवधि के लिए भर्ती को समायोजित करने के बाद कानून के अनुसार एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए उत्तरदाताओं । से 3 तक आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति

भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 24(2)-प्रशा. में निर्धारित कोटा नियम। आईटी/51 दिनांक 18 अक्टूबर 1951। हालांकि, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह आदेश ऐसे वर्ग ।। अधिकारियों को प्रभावित नहीं करेगा जिन्हें स्थायी रूप से सहायक आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन यह आदेश उन सभी अधिकारियों सहित अन्य सभी अधिकारियों पर लागू होगा जिन्हें उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अस्थायी रूप से सहायक आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

इस संदर्भ में इस बात पर जोर देना जरूरी है कि मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन की पहली अनिवार्यता है जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था आधारित है। कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली में, विवेक, जब कार्यकारी प्राधिकारियों को दिया जाता है, तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर ही सीमित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कानून के शासन का अर्थ है कि निर्णय ज्ञात सिद्धांतों और नियमों को लागू करके किए जाने चाहिए और सामान्य तौर पर, ऐसे निर्णय पूर्वानुमानित होने चाहिए और नागरिक को पता होना चाहिए कि वह कहां है। यदि कोई निर्णय बिना किसी सिद्धांत या बिना किसी नियम के लिया जाता है तो यह अप्रत्याशित होता है और ऐसा निर्णय कानून के शासन के अनुसार लिए गए निर्णय के विपरीत होता है। (देखें डाइसी-"संविधान का कानून"-दसवां संस्करण, परिचय पूर्व)। डगलस, जे. ने कहा, "कानून अपने सर्वोत्तम क्षणों तक पहुंच गया है"। युनाइटेड स्टेट्स बनाम वंडरलिक(1),

"जब इसने मनुष्य को किसी शासक के असीमित विवेक से मुक्त कर दिया है... जहां विवेक; निरपेक्ष, मनुष्य को हमेशा कष्ट सहना पड़ा है"। इसी अर्थ में कानून के शासन को सनक का कट्टर शत्रु कहा जा सकता है। विवेक, जैसा कि लॉर्ड मैन्सफील्ड ने जॉन विल्क्स (2) के मामले में क्लासिक शब्दों में कहा था, "का अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित ध्वनि विवेक। इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि हास्य द्वारा: यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए।"

हमें सरकार को यह भी सुझाव देना चाहिए कि भविष्य के वर्षों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच कोटा निर्धारित करने के लिए एक उचित नियम बनाकर रोस्टर प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए और नियुक्तियों के क्रम को दर्शाते हुए एक रोस्टर बनाए रखा जाना चाहिए। भर्ती की प्रत्येक विधि के लिए वैधानिक नियम के तहत निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा किया जाता है।

इन कारणों से हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और आदेश देते हैं कि ऊपर बताई गई सीमा तक अपीलकर्ता को परमादेश की प्रकृति की रिट दी जानी चाहिए। इस अपील में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

रिट याचिका संख्या 5, 1966

इस याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और अनुच्छेद के तहत परमादेश की प्रकृति में एक रिट दी जानी चाहिए । संविधान के 32 में उत्तरदाताओं 1 से 3 को याचिकाकर्ता और उसके जैसे अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता को समायोजित करने और 1951 से 1956 और उसके बाद की अवधि के लिए भर्ती को समायोजित करने के बाद कानून के अनुसार एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिया जाना चाहिए। पत्र क्रमांक एफ 24(2) प्रशासन में निर्धारित कोटा नियम के अनुसार। भारत सरकार का आईटी/51 दिनांक 18 अक्टूबर 1951। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

वी.पी.एस

याचिका मंजूर.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अशोक सेन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।